हिन्दी साप्ताहिक

R.N.I. No. UPHIN/2022/83621

जनता का सच

वर्ष 05 अंक 33 | लखनऊ शनिवार 22 अगस्त 2026 | पृष्ठ 04 मूल्य 2 रूपया

पांच घंटे बाद राहुल की मांग मानी पैलेट गन मामले में प्राथमिकी दर्ज

घायल छात्र साहिल लोचव की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस; संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे थे राहुल

नई दिल्ली,एजेंसी। छात्र आंदोलन के दौरान कथित रूप से पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला अब कानूनी जांच के दायरे में आ गया है। दिल्ली पुलिस ने घायल छात्र साहिल लोचब की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मामले में लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे और शुक्रवार को साहिल के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचकर धरने पर बैठ गए थे। कई घंटे चले घटनाक्रम के बाद पुलिस के प्राथमिकी दर्ज करने पर सहमत होने को राहुल गांधी की बड़ी राजनीतिक और कानूनी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। मामला 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन से जुड़ा है। नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्र संगठनों ने 'संसद चलो' मार्च निकाला था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तनाव बढ़ा और बल प्रयोग की स्थिति बनी। इसी दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल का आरोप सामने आया। छात्र साहिल लोचब गंभीर रूप से घायल हुए थे। साहिल के परिवार और छात्र संगठनों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान उनके शरीर पर बड़ी संख्या में छर्रे लगे। मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि साहिल के चेहरे, गर्दन, छाती और आंखों में 200 से अधिक छर्रे लगे। सबसे गंभीर चोट उनकी दाईं आंख में बताई गई है। आरोप है कि आंख में कई छर्रे भीतर तक धंस गए, जिससे उनकी दृष्टि लगभग पूरी तरह प्रभावित हो गई। घटना के बाद से राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे। उन्होंने सवाल किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पैलेट गन जैसी गंभीर कार्रवाई का आदेश किसने दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि यदि किसी छात्र की आंख की रोशनी चली गई है और वह गंभीर रूप से घायल हुआ है तो उसकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है। शुक्रवार को राहुल गांधी साहिल और उसके परिवार के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। तत्काल कार्रवाई नहीं होने पर राहुल गांधी थाने में ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए। कुछ घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने साहिल की शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब जांच का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि 20 जुलाई को छात्र आंदोलन के दौरान वास्तव में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। यदि इसका इस्तेमाल हुआ तो किसके आदेश पर किया गया ।

गिरगिट की तरह रंग बदलती है सपा: योगी

पूर्व सीएम कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

लखनऊ,संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले पार्टी के लोग पीडीए को कैसे परिभाषित करते हैं, कभी इनका पी पिछड़ा था, फिर पंडित हो गया। देखना एक दिन ये लोग पी से पाकिस्तान कर देंगे। इनके बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कब क्या बोलेंगे, कोई भरोसा नहीं। ये ऐसे गिद्ध हैं कि जिस पेड़ पर चढ़ेंगे, उसको ही सुखा डालेंगे। सबसे कष्टकारी बात यह थी कि सामान्य शिष्टाचार व संस्कार के तहत मायावती ने आकर बाबूजी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन सपा मुखिया ने प्रत्यक्ष आकर श्रद्धांजलि देना तो दूर, शब्दों से भी कुछ व्यक्त नहीं किया। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण, कितना शर्मनाक है। यह हर उस हिंदू का अपमान था, जिसे लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों और हिंदू गौरव के लिए समर्पित था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण कल्याण सिंह की पांचवीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित 'हिंदू गौरव दिवस' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे पद्म विभूषण कल्याण सिंह 'बाबूजी' की पांचवीं पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पार्चन कर अपनी श्रद्धांजलि दी। श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबूजी दबाव में आकर काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे। वह कहा करते थे, कल्याण सिंह टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। बाबूजी ने जीवनभर अपने इस वचन को निभाया। जन्मभूमि आंदोलन के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा था कि संघर्ष स्वीकार्य है, सत्ता दूर हो जाए यह भी स्वीकार है, लेकिन अपने प्रभु श्रीराम का अपमान स्वीकार्य नहीं। आज जब हम लोग अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला का विराजमान होना देखते हैं तो बाबूजी की स्मृति सहसा अंतःकरण में उठती है। संतों के संघर्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में चले राम जन्मभूमि आंदोलन का कल्याण सिंह जी ने खुलकर समर्थन किया। उन्होंने सत्ता गंवाई, लेकिन दो-टूक कहा कि रामभक्तों पर गोली नहीं चलेगी सीएम योगी ने कहा कि बाबूजी ने मूल्यों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, यही उनकी पहचान थी। सपा नेतृत्व ने सिर्फ बाबूजी के निधन के समय अपमान नहीं किया, महापुरुषों का अपमान उसकी आदत है। कन्नौज से समाजवादी पार्टी का रिश्ता रहा है, लेकिन वहां डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम पर बने सरकारी मेडिकल कॉलेज से सपा मुखिया ने बाबा साहेब का नाम हटा दिया। हमारी सरकार में इसे फिर से बाबा साहेब के नाम पर किया गया। मैनपुरी में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर एक कॉलेज बना था, लेकिन सपा ने उनका नाम भी मिटा दिया। भाजपा सरकार ने औरैया में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया। सीएम योगी ने कहा कि श्रद्धेय कल्याण सिंह का जीवन हर उस भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत है, जिसके लिए देश प्रथम है। भारत के सनातन मूल्य एवं आदर्श सर्वोपरि हैं। आज का दिन हम सभी के लिए हिंदू गौरव दिवस के रूप में श्रद्धेय बाबूजी की स्मृतियों को प्रेरणा के रूप में आत्मसात करने का दिन है। बड़ा आदमी पद से बड़ा नहीं होता है, वह अपनी सोच से, अपने कर्मों से बड़ा होता है और महान होता है। अतरौली के सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने वाले कल्याण सिंह जी अपनी कर्मठता, मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने की भावना तथा देश के प्रति समर्पण के कारण आगे बढ़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में तपे स्वयंसेवक के रूप में कल्याण सिंह जी ने किसान, शिक्षक, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और राज्यपाल के रूप में सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। बाबूजी का जीवन सादगी, तप, साधना और संघर्ष से भरा हुआ था।

भारत-जापान की साझेदारी खोलेगी नई संभावनाएं: योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोतारो नागासाकी के नेतृत्व में आए जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश, तकनीक, शिक्षा, हरित विकास और सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और जापान की ताकत जब एक साथ आएगी तो इसका लाभ केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जापानी कंपनियों के निवेश की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। अवस्थापना विकास, औद्योगिक गलियारों, एक्सप्रेसवे, बेहतर संपर्क व्यवस्था और निवेश संबंधी नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख निवेश स्थलों में शामिल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ हरित ऊर्जा, टिकाऊ विकास, नई तकनीक और औद्योगिक सहयोग के क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और जापान मिलकर ऐसे विकास मॉडल पर काम कर सकते हैं, जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बराबर महत्व मिले।

सिविल जज भर्ती में अब एक साल की ही प्रैक्टिस जरूरी

ग्रेटर नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती के लिए वकालत के अनुभव की अनिवार्य अवधि तीन साल से घटाकर एक साल कर दी है। कोर्ट के इस फैसले से न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा अधिवक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सेवा में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए व्यावहारिक अनुभव जरूरी है, लेकिन तीन साल की लंबी अनिवार्यता से युवा वकीलों के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। अब सिविल जज भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम एक साल की वकालत का अनुभव होना आवश्यक होगा। इस फैसले का असर देशभर में होने वाली सिविल जज भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ेगा और बड़ी संख्या में युवा अधिवक्ता अब पहले की तुलना में जल्दी न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए पात्र हो सकेंगे।

जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण में काला धन खपाने के सुराग

ग्रेटर नोएडा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके परिवार से जुड़े जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर काला धन खपाए जाने और सरकारी धन के दुरुपयोग के सुराग प्रवर्तन निदेशालय को मिले हैं। हाल में विश्वविद्यालय, ट्रस्ट पदाधिकारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और संबंधित कंपनियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी में मिले दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जांच एजेंसी को संदेह है कि सांसद-विधायक निधि और विभिन्न सरकारी विभागों से विकास कार्यों के लिए जारी धन का इस्तेमाल जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में किया गया। सूत्रों के मुताबिक जल निगम, लोक निर्माण विभाग, ग्राम्य विकास, संस्कृति, पिछड़ा वर्ग, नगर विकास और सिंचाई विभाग से जुड़े तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। ईडी की जांच में छह ऐसे ठेकेदारों की भूमिका सामने आई है, जिन्होंने सरकारी योजनाओं के तहत काम हासिल किए थे। आरोप है कि सरकारी धन बैंक खातों से निकालकर विश्वविद्यालय और जौहर ट्रस्ट की संपत्तियों के निर्माण में लगाया गया।

सरकार का लक्ष्य आम लोगों के जीवन को आसान बनाना है

दुनिया भारत को विकास और उम्मीद की चमकती किरण के रूप में देख रही : प्रधानमंत्री मोदी

नयी दिल्ली एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया भारत को विकास और उम्मीद की चमकती किरण के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि भारत राजनीतिक स्थिरता और नीतियों में निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य अगले स्तर के सुधारों के जरिये देश में कारोबार, रोजगार और आम लोगों के जीवन को आसान बनाना है।प्रधानमंत्री ने यहां इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम-2026 को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष सम्मेलन की थीम 'शेयर्ड फ्यूचर्स' यानी साझा भविष्य आज की वैश्विक परिस्थितियों में बेहद प्रासंगिक है। दुनिया में बढ़ते अविश्वास, संसाधनों के हथियारीकरण और आर्थिक चुनौतियों के बीच सभी देशों का भविष्य एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान भी 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का मंत्र इसी भावना को दर्शाता था। मोदी ने कहा कि भारत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और वह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में बताए गए 'सप्तधारा' के तहत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित सात प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत नीतिगत, शासन स्तर और ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में अगली पीढ़ी के सुधार कर रहा है। सुधार भारत के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता और विश्वास हैं। प्रधानमंत्री ने लाइसेंस राज के दौर की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय उत्पादन बढ़ाने पर कंपनियों को दंडित किया जाता था। उन्होंने इसे 'प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट' (पीएलपी) की मानसिकता बताया। इसके विपरीत आज सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने कहा कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश आया है, जबकि 22 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और बिक्री हुई है। इस योजना से 15 लाख करोड़ रुपये का निर्यात और 14 लाख से अधिक रोजगार पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की दंड आधारित व्यवस्था जहां बेरोजगारी बढ़ाती थी, वहीं आज की प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था लाखों नए रोजगार पैदा कर रही है। मोदी ने कहा कि भारत की तेज विकास गति के पीछे राजनीतिक स्थिरता और नीतियों में निरंतरता महत्वपूर्ण कारण हैं। सरकार ने 'जब तक अनुमति न हो, तब तक प्रतिबंधित' की पुरानी सोच की जगह 'जब तक प्रतिबंधित न हो, तब तक अनुमति' की व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार और नागरिकों के बीच संबंध का आधार संदेह नहीं बल्कि विश्वास होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन विश्वास विधेयक के जरिये कई छोटे प्रक्रियात्मक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। साथ ही 40 हजार से अधिक अनुपालनों को समाप्त किया गया और 1,500 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे कारोबार पर पड़ने वाला बोझ कम हुआ है। उन्होंने मानसून सत्र में बैंकर्स बुक्स एविडेंस कानून में किए गए बदलाव का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 19वीं सदी के ब्रिटिश कानून की जगह डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाली आधुनिक व्यवस्था से कानूनी जटिलताएं कम होंगी और कारोबार करना आसान होगा।

यूएससीआईआरएफ की कोई साख नहीं, नजरअंदाज करें : भारत

नई दिल्ली,एजेंसी। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अमेरिकी संस्था 'यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' (यूएससीआईआरएफ) की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि संस्था का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का इतिहास रहा है। विदेश मंत्रालय का यह बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की अमेरिकी यात्रा के संबंध में संस्था की ओर से की गई टिप्पणियों के संदर्भ में था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि संस्था के बारे में सबको पता है। वह पक्षपाती है और कई सालों से भारत के बारे में उल्टी-सीधी बातें करती आई है। संस्था भारत के खिलाफ भड़काने वाली बातें भी करती रही है। उसकी कोई साख व विश्वसनीयता नहीं है। वे बस इतना कहना चाहेंगे कि हमें ऐसे संस्थानों से दूर रहना चाहिए।उल्लेखनीय है कि यूएससीआईआरएफ अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट और सिफारिशें देने वाली संस्था है। भारत सरकार इससे पहले भी उसकी कई रिपोर्टों और टिप्पणियों को पक्षपातपूर्ण बताते हुए अस्वीकार करती रही है।

'जयपुर डिक्लेरेशन' से दुनिया के पर्यटन नक्शे पर और चमकेगा जयपुर

जयपुर। गुलाबी नगरी की ऐतिहासिक विरासत अब सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि ब्रिक्स देशों के पर्यटन सहयोग की वैश्विक पहचान भी बनेगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 'जयपुर डिक्लेरेशन' केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन सहयोग को जमीन पर उतारने की साझा प्रतिबद्धता है। अंतरराष्ट्रीय घोषणा से जयपुर का नाम जुड़ना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और इससे जयपुर की वैश्विक पर्यटन पहचान को मजबूती मिलेगी।

सिलीगुड़ी में कानूनी प्रदर्शनी का उद्घाटन

'डर नहीं, भरोसे की सरकार' का होगा शासन: शाह

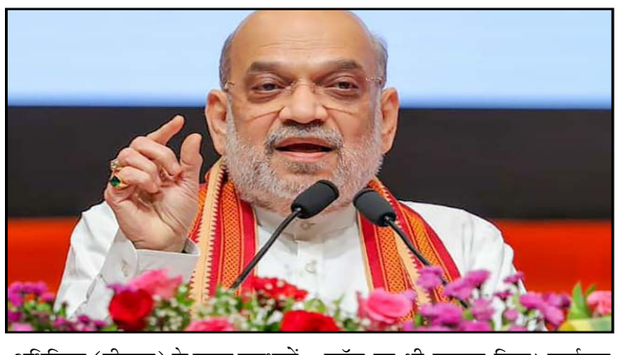

सिलीगुड़ी,(एजेंसी)। उत्तर बंगाल के प्रवेशद्वार सिलीगुड़ी में नए आपराधिक कानूनों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को विशाल कानूनी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कावाखाली मैदान में '5 स्तंभ – बदली हुई न्याय व्यवस्था' थीम पर आयोजित 'न्याय संहिता प्रदर्शनी' का उद्घाटन किया।यह प्रदर्शनी 21 से 26 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य पुराने भारतीय दंड संहिता (1860), दंड प्रक्रिया संहिता (1973) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) की जगह लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के प्रमुख प्रावधानों और बदलावों को आम लोगों के सामने सरल तरीके से रखना है। उद्घाटन के बाद अमित शाह ने प्रदर्शनी के विभिन्न स्टॉल का भी जायजा लिया। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, मंत्री निशीथ प्रमाणिक, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जलपाईगुड़ी, इस्लामपुर और दार्जिलिंग के विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी प्रदर्शनी में लाया गया। खुले मंच से संबोधित करते हुए अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि देशभर में नए न्याय कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई। शाह ने आरोप लगाया कि नए कानून लागू होने से सिंडिकेट, धन उगाही, वसूली और भय का माहौल खत्म हो जाएगा। चुनाव के दौरान भाजपा ने बंगाल की जनता से 'डर की नहीं, भरोसे की सरकार' देने का वादा किया था। शाह के मुताबिक, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पद संभालने के बाद जिन शुरुआती फाइलों पर हस्ताक्षर किए, उनमें तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने से संबंधित फाइल भी शामिल थी। अमित शाह ने नए कानूनों में तकनीक के इस्तेमाल को महत्वपूर्ण बदलाव बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में तकनीक आधारित साक्ष्यों का अधिक इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे जांच और न्याय प्रक्रिया को गति मिलेगी। उन्होंने जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर जैसी व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया। शाह के अनुसार, इन प्रावधानों से देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों को शिकायत दर्ज कराने में सुविधा होगी और मामलों को संबंधित थाने तक पहुंचाने की प्रक्रिया आसान होगी।

10 से 14 महीने में बाजार में आ सकता है नया भारतीय मोबाइल ब्रांड :अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि अगले 10 से 14 महीनों में एक मजबूत भारतीय मोबाइल ब्रांड बाजार में आ सकता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल तीन संभावित कंपनियां भारतीय ब्रांड विकसित करने की दिशा में काम कर रही हैं। हालांकि, उन्होंने इन कंपनियों के नाम बताने से इनकार किया।वैष्णव ने नई मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) के शुभारंभ के मौके पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत ने मोबाइल फोन के निर्माण के क्षेत्र में मजबूत आधार तैयार कर लिया है और अब अगला लक्ष्य अपने भारतीय ब्रांड, भारतीय डिजाइन और अपनी तकनीक विकसित करना है। नई योजना एक अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी और पांच साल तक चलेगी। इसके लिए 62,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि भारतीय मोबाइल ब्रांड तैयार करने के लिए डिजाइन भारत का और संबंधित कंपनी के स्वामित्व वाला होना चाहिए। उत्पाद किसी दूसरे ब्रांड की नकल नहीं होना चाहिए। सरकार भारतीय कंपनियों से ऐसा डिजाइन तैयार करने की उम्मीद कर रही है, जो अपने बाजार वर्ग में दुनिया के बेहतर उत्पादों से मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा कि तीन संभावित कंपनियों को डिजाइन तैयार करने की दिशा में काम करने के लिए कहा गया है। कंपनियों को किफायती, प्रीमियम या अन्य श्रेणियों में से अपना बाजार चुनना होगा। वैष्णव ने कहा कि भारतीय ब्रांड के लिए अपनी तकनीक और बौद्धिक संपदा विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण है और इस मामले में सरकार कोई समझौता नहीं करेगी।

छात्रों ने कई मुद्दों पर बुनियादी बदलाव का मैसेज दिया

अपर्याप्त बजट का नतीजा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, शाला भवनों की दुर्दशा और अन्य सुविधाओं के अभाव में सामने आया है। विशेष रूप से छोटे शहरों और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के स्कूल ज्यादा अभावग्रस्त हैं। शिक्षा के प्रति सरकारों की उपेक्षा को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर कर सकते हैं। देश में 2014-15 से 2024-25 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या 94 हजार कम हुई है। इसमें उन स्कूलों की संख्या शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकारें किसी अन्य स्कूल में शामिल करती हैं। अच्छी बात यह है कि इस दरम्यान शिक्षकों की संख्या में 11 लाख से अधिक इजाफा हुआ है। इन स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या दो करोड़ 26 लाख कम हो गई थी।

राजेश पांडेय
****

20 जून को जंतर-मंतर, नई दिल्ली से शुरू हुए छात्रों के आंदोलन की आवाज देश के कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश,राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश सहित कई राज्यों में विद्यार्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया और रैलियां निकाली हैं। कहीं बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, स्कूलों में शिक्षकों और जरूरी सुविधाओं की कमी, तो कहीं होस्टल की ज्यादा फीस जैसे मुद्दों ने छात्रों को सड़क पर आने के लिए प्रेरित किया है। बदलाव और बेचैनी की ऊर्जा से भरी यह हलचल हमारे समाज, राजनीति और सरकारी तंत्र को वर्तमान दौर की चुनौतियों को समझने और उसके हिसाब से कदम उठाने का स्पष्ट संदेश देती है। इन आंदोलनों ने कुछ अहम पहलुओं को रेखांकित किया है। कुछ नए ट्रेंड उभर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहे। आमतौर पर किसी मुद्दे, मांग या विषय के पक्ष-विपक्ष में जनता के विभिन्न वर्ग बड़े शहरों में एकजुट होते आए हैं। अक्सर राजनीतिक दलों, छात्रों, मजदूर संघों और सामाजिक संगठनों द्वारा जनमत जगाने, विरोध जताने और लोगों को संगठित करने की मुहिम राजधानियों या बड़े शहरों में आकार लेती है। बहुत व्यापक आंदोलनों को छोड़ दें तो कई बार वह उन्हीं स्थानों तक सिमटकर रह जाती है। इस बार स्थिति अलग है। दिल्ली, भोपाल, रायपुर जैसी राजधानियों से उठी आवाज की अनुगूंज छोटे शहरों में सुनाई पड़ रही है। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले लोगों के स्वरूप में हुआ है। कॉलेज छात्रों के साथ स्कूली छात्र आगे आए हैं। स्कूली छात्र सिर्फहाईस्कूल तक सीमित नहीं हैं। कई जगह मिडिल स्कूल के छात्रों ने सीनियर साथियों के साथ मोर्चा संभाला है। लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। वे सिर्फदिल्ली या राजधानियों में ही नहीं छोटे शहरों तक में सड़क पर उतरी हैं। सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? जाहिर है, वे मौजूदा स्थितियों में अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं हैं। उन्हें जिंदगी की दौड़ में पिछड़ने का खतरा नजर आता होगा। छोटे शहरों के छात्रों के जागरूक होने का मुख्य कारण उनकी मांग तो है ही पर सोशल मीडिया ने उनके लिए कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। मोबाइल के परदे का छोटा स्क्रीन उन्हें दिल्ली से लेकर सैनफ्रांसिस्को तक की हलचल की जानकारी देता है। वे सिर्फरील बनाने, देखने या मनोरंजन तक सीमित नहीं होंगे। उन्हें साइंस, टेक्नालॉजी, इनोवेशन से जुड़ी गतिविधियों की खबरें मिल रही हैं। स्पेस साइंस के चमत्कार भी उनकी कल्पनाओं का हिस्सा बन रहे होंगे। वे देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका के कोई मार्क जकरबर्ग फेसबुक, व्हाट्सएप जैसा टूल बनाते हैं तो कैसे ओपन एआई के सैम आल्टमैन चौट जीपीटी पेश कर रहे हैं। वे यह भी जानने लगे हैं किस तरह मेडिकल साइंस ने दिल और मस्तिष्क के रोगों सहित कई लाइलाज बीमारियों में राहत देने का रास्ता खोज लिया है। सूचना क्रांति का वर्तमान समय छात्रों सहित हर किसी को लोकतंत्र, आजादी और खुलेपन की अहमियत बताता है। वह उनके अंदर सिस्टम की जड़ता को तोड़ने और नई राह पर चलने की बेचैनी पैदा करता है। उन्हें कहीं लगता है कि वे असली बदलाव से बहुत दूर हैं। युवा महसूस कर रहे हैं कि मौजूदा व्यवस्था उन्हें सिर्फ प्रतियोगिता की अंतहीन होड़ में झोंक रही है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था को नैतिकता, ईमानदारी, विश्वसनीयता और मानवीय मूल्यों के प्रसार का वाहक होना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। हम हर कहीं मूल्यों का क्षरण देखते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा अपने पुराने ढर्रे पर चल रहा है। ऐसे सिस्टम से युवाओं का मोहभंग और हताशा स्वाभाविक है। आधुनिक दौर में ऐसी व्यवस्था के खिलाफताकतवर स्वर उभरते रहे हैं। युवाओं और आम लोगों ने समय-समय पर सत्ता को झकझोरने के लिए अपना असंतोष जाहिर किया है। छात्रों के सत्याग्रह का जिक्र होता है तो मार्च, मई 1968 में फ्रांस के छात्र आंदोलन को हमेशा याद किया जाता है। उस वक्त पेरिस में छात्रों ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में छात्रों की भीड़, शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त साधनों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। देश की ट्रेड यूनियन भी छात्रों के साथ खड़ी हो गई थीं। आंदोलन दूसरे शहरों में फैल गया। मजदूर संघों के साथ आने से कारखानों, दफ्तरों में काम ठप पड़ गया था। फ्रांस के आंदोलन में तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डिगाल की दस साल लंबी सत्ता का विरोध भी जुड़ा था। डिगाल का शासन अनुदारवादी था। उनकी तानाशाही और मनमानी के खिलाफनौजवानों और मजदूर वर्ग में असंतोष पनप रहा था। डिगाल ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने नेशनल असेम्बली भंग कर दी। नए चुनाव कराए। देश में फैली अस्थिरता से परेशान मध्यम वर्ग ने डिगाल का समर्थन किया। उनकी पार्टी को संसद में फिर बहुमत मिल गया। 1969 में डिगाल ने संसद के स्वरूप में बदलाव के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया। लेकिन जनमतसंग्रह में हारने पर अप्रैल में उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। भारत में विभिन्न स्तरों पर चल रही छात्रों की हलचल का संबंध व्यवस्था विरोधी भी है। निश्चित रूप से वह स्कूल, कॉलेजों में साधनों के अभाव से जुड़ा है। शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों का खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.8 से 4.3 प्रतिशत के बीच चल रहा है। वैसे, राष्ट्रीय नीति में शिक्षा पर जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने की नीति रही है।

संम्पादकीय

जम्मू-कश्मीर पर अमेरिकी राजदूत का बयान

अमेरिका के भारत में राजदूत, साथ ही दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गोर ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर का पहली बार दौरा किया। गोर ने जम्मू-कश्मीर को ≠भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा≠ बताया। जो हर तरीके से सही बयान है, लेकिन इस बयान को देने का वक्त और इसके पीछे अमेरिका की मंशा इन सब पर अब सवाल उठ रहे हैं। खासकर जिस तरह पाकिस्तान में इस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है, वह जाहिर कर रही है कि मामला केवल इतना ही नहीं है। क्योंकि सर्जियो गोर ने कोई ऐसी बात नहीं कही, जो दुनिया नहीं जानती। लेकिन पाकिस्तान इस बात को हमेशा नकारता है और जम्मू-कश्मीर पर अपना दावा ठोंकता रहता है। इसी वजह से कई बार दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़े हैं। अतीत में कई बार अमेरिका पाकिस्तान के पलड़े की तरफझुका दिखाई दिया है। हालांकि भारत ने तब भी बिना दबाव में आए यही दावा किया है कि जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और पाकिस्तान के साथ विवाद को दोनों पक्ष ही मिलकर सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरे के लिए स्थान नहीं है। मगर डोनाल्ड ट्रंप बार-बार किसी न किसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच आ ही जाते हैं। पहलगाम हमलों के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने सौ से ज्यादा बार किया है। पाकिस्तान ने भी बाकायदा ट्रंप को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मगर भारत ने इस बात को नहीं माना कि उसने किसी के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर बंद किया। खेद इस बात का है कि नरेन्द्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब नहीं दिया कि आप ऐसे दावे न करें, यह सही नहीं है। अगर मोदी ऐसा करते तो शायद इस समय अमेरिकी राजदूत जम्मू-कश्मीर पर अपना प्रमाणपत्र नहीं देते और न सत्तारुढ़ भाजपा उसे लपक कर लेती। भाजपा ने गोर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि ≠सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। यह एक स्पष्ट संदेश है, जिसे जमीन पर स्वीकार किया गया है और दुनिया ने भी मान्यता दी है। भाजपा इस उतावलेपन की जगह अगर केवल यही लिखती कि जो बात जगजाहिर है, वही सर्जियो गोर ने कही है, तो बेहतर रहता। बहरहाल, सर्जियो गोर के बयान के बाद भारत, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अब कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। बुधवार से लेकर गुरुवार तक तीन अहम घटनाएं घटित हुईं, पहली सर्जियो गोर का बयान, दूसरी, पाकिस्तान का अमेरिकी राजनयिक को तलब करना और तीसरी दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त के बाहर सुरक्षा ढांचे हटाया जाना। बता दें कि पाकिस्तान ने इस बयान को लेकर इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रभारी राजदूत नताली बेकर को तलब किया और अपना विरोध दर्ज कराया। इसी बीच नयी दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड, ट्रैफिक बोलार्ड और कतार नियंत्रित करने वाले ढांचे भी हटा दिए गए हैं। हालांकि करीब तीन दिन पहले पाकिस्तान में इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त के बाहर सुरक्षा बैरिकेड हटाए गए थे।

कश्मीर पर अमेरिकी सुर बदले: भारत का कद बढ़ा, पाक बेचैन

ललित गर्ग
****

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का 19 अगस्त 2026 को श्रीनगर में दिया गया यह बयान कि जम्मू-कश्मीर ÷भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा÷ है, सामान्य कूटनीतिक टिप्पणी मानकर नजरअंदाज करने योग्य नहीं है। यह ऐसे समय आया है जब कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान की धारणाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार नए समीकरण बन रहे हैं। गोर ने जम्मू-कश्मीर की निरन्तर सुधर रही सुरक्षा स्थिति की बात कही और अमेरिकी यात्रा संबंधी परामर्श पर पुनर्विचार के संकेत भी दिए। पाकिस्तान ने इस बयान पर अमेरिका के शीर्ष राजनयिक को तलब कर तीखा विरोध दर्ज कराया। इस पूरे घटनाक्रम को केवल कश्मीर के संदर्भ में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसे भारत-अमेरिका संबंधों में आ रहे व्यापक परिवर्तन, दक्षिण एशिया की बदलती सामरिक संरचना और पाकिस्तान की घटती कूटनीतिक प्रभावशीलता के संदर्भ में समझना अधिक उचित होगा। अमेरिका की कश्मीर नीति में लंबे समय से एक प्रकार की सावधानी रही है। वाशिंगटन सामान्यतः भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद तथा शांतिपूर्ण समाधान की बात करता रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की पूर्व घोषित नीति भी जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति और राजनीतिक-आर्थिक स्थिरता की वापसी का समर्थन करती रही है। इसलिए गोर का श्रीनगर में जाकर जम्मू-कश्मीर को भारत का ÷महत्वपूर्ण हिस्सा÷ कहना निश्चित रूप से भाषा के स्तर पर एक उल्लेखनीय परिवर्तन है। लेकिन इसे

अमेरिका की पूरी कश्मीर नीति में तत्काल और औपचारिक परिवर्तन मानना भी जल्दबाजी होगी। किसी राजदूत का बयान और किसी सरकार की औपचारिक नीति में अंतर होता है। फिर भी कूटनीति में शब्दों का अपना महत्व होता है। विशेष रूप से तब, जब वही शब्द उस भूभाग में बोले जाएं जिसे पाकिस्तान दशकों से अंतरराष्ट्रीय विवाद के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। इस दृष्टि से गोर का बयान भारत के लिए मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। इस बयान का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जम्मू-कश्मीर की बदलती जमीन से जुड़ा है। गोर ने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार का उल्लेख करते हुए यात्रा संबंधी अमेरिकी परामर्श में कमी लाने की संभावना जताई है। इसका अर्थ यह है कि वाशिंगटन अब कश्मीर को केवल सुरक्षा संकट या आतंकवाद की दृष्टि से देखने के बजाय पर्यटन, आर्थिक गतिविधियों और सामान्य जनजीवन की संभावनाओं वाले क्षेत्र के रूप में भी देख रहा है। यहीं से भारत-अमेरिका संबंधों की नई रोशनी दिखाई देती है। दोनों देशों के संबंध अब केवल व्यापार या रक्षा तक सीमित नहीं हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, आपूर्ति-श्रृंखला और वैश्विक शक्ति-संतुलन जैसे विषयों ने भारत को अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार और शुल्क जैसे मुद्दों पर मतभेद भी मौजूद हैं, फिर भी व्यापक सामरिक साझेदारी अपनी उपयोगिता बनाए हुए है। हाल में अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा का उद्देश्य भी तनावों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना और व्यापार तथा ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाना था। इसलिए कश्मीर पर अमेरिकी भाषा को भारत-अमेरिका संबंधों के व्यापक पुनर्संतुलन का हिस्सा मानना अधिक तार्किक होगा। अमेरिका के लिए भारत अब केवल दक्षिण एशिया का एक बड़ा देश नहीं, बल्कि एशिया में शक्ति-संतुलन का प्रमुख आधार है। भारत के लिए भी अमेरिका महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति को किसी एक शक्ति के साथ पूर्ण निर्भरता के बजाय रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रखा है। यही कारण है कि भारत अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ाते हुए रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया और अन्य शक्तियों के साथ भी अपने संबंध बनाए रखता है। कश्मीर के संदर्भ में यह घटनाक्रम पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से असहज करने वाला है। इस्लामाबाद ने गोर के बयान को अस्वीकार करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और उसका अंतिम निर्धारण होना बाकी है। पाकिस्तान ने इसे अमेरिका की पूर्व स्थिति से विचलन बताते हुए औपचारिक विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान की समस्या यह है कि वह कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी विदेश नीति का केंद्रीय विषय बनाए रखना चाहता है, जबकि विश्व राजनीति की प्राथमिकताएं तेजी से बदल रही हैं। आतंकवाद, आर्थिक स्थिरता, चीन का बढ़ता प्रभाव, पश्चिम एशिया का संकट, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति-शृंखलाएं आज बड़ी शक्तियों की चिंता के केंद्र में हैं। ऐसे वातावरण में केवल कश्मीर के प्रश्न को बार-बार अंतरराष्ट्रीयकरण करने की पाकिस्तानी कोशिशों की प्रभावशीलता सीमित होती जा रही है। भारत ने दूसरी ओर लगातार यह रेखांकित किया है कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े विषय भारत की संप्रभुता और द्विपक्षीय संबंधों के दायरे में आते हैं। गोर का श्रीनगर दौरा स्वयं इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि एक प्रमुख अमेरिकी राजनयिक ने जम्मू-कश्मीर की यात्रा की, वहां के निर्वाचित नेतृत्व से मुलाकात की और क्षेत्र की सुरक्षा तथा आर्थिक संभावनाओं पर सकारात्मक टिप्पणी की। यह पाकिस्तान की उस कोशिश के विपरीत है जिसमें वह कश्मीर को केवल विवाद और अस्थिरता के चश्मे से प्रस्तुत करना चाहता है। फिर भी भारत को इस बयान से अत्यधिक उत्साहित होकर यह मान लेने से बचना चाहिए कि अमेरिका ने कश्मीर पर अपनी संपूर्ण नीति बदल दी है। अमेरिका की विदेश नीति परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है और वह भारत तथा पाकिस्तान दोनों के साथ अपने हितों को संतुलित करने की कोशिश करता है। आज भी वाशिंगटन के लिए पाकिस्तान आतंकवाद-रोध, क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान सहित कुछ विषयों में उपयोगी साझेदार है। अतः भारत के लिए इस बयान का वास्तविक महत्व किसी औपचारिक अमेरिकी नीति-परिवर्तन से अधिक उस कूटनीतिक वातावरण में है, जिसमें भारत की स्थिति को पहले की तुलना में अधिक गंभीरता से लिया जा रहा है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। कूटनीति में किसी देश का महत्व केवल इस बात से तय नहीं होता कि कितने देश उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं, बल्कि इससे तय होता है कि वैश्विक शक्तियों के हित उसके साथ कितने गहरे जुड़े हैं। आज भारत की आर्थिक क्षमता, विशाल बाजार, तकनीकी सामर्थ्य, लोकतांत्रिक संस्थाएं, युवा शक्ति और सामरिक स्थिति उसे विश्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बनाती हैं। इसी बदलती वास्तविकता का प्रभाव कश्मीर पर भी दिखाई देना स्वाभाविक है। गोर का बयान इसलिए भारत के लिए एक उपलब्धि से अधिक एक संकेत है- संकेत इस बात का कि जम्मू-कश्मीर को लेकर अंतरराष्ट्रीय विमर्श धीरे-धीरे बदल रहा है। पाकिस्तान के लिए यह चेतावनी है कि केवल पुराने नारों और कूटनीतिक दबाव से वह कश्मीर को विश्व राजनीति के केंद्र में नहीं रख सकता और अमेरिका के लिए यह उसके बदलते हितों के अनुरूप संतुलन साधने की कोशिश है। अंततः कश्मीर की स्थायी शांति केवल अंतरराष्ट्रीय बयानों से नहीं, बल्कि लोकतंत्र, विकास, सुरक्षा, जनभागीदारी और सीमा-पार आतंकवाद के अंत से सुनिश्चित होगी। भारत को इस नए कूटनीतिक वातावरण का उपयोग आक्रामक प्रचार के बजाय जिम्मेदार और आत्मविश्वासी राष्ट्र की तरह करना चाहिए। सर्जियो गोर का बयान इस बदलती तस्वीर की एक महत्वपूर्ण झलक है-जहां कश्मीर को लेकर भारत की स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता प्राप्त करती दिखाई दे रही है और पाकिस्तान की कूटनीतिक चुनौती पहले से अधिक कठिन होती जा रही है।

आज का राशिफल

मेष	निकट संबंधों में शंकाओं को हावी न होने दें। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति होने के आसार बनेंगे। नौकरी का वातावरण सुखद होगा। सगे-संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी।
वृषभ	आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार हैं। अवरोधित कार्य हल होंगे। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी।
मिथुन	आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार हैं। अवरोधित कार्य हल होंगे। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी।
कर्क	बीती बातों को भूलने की कोशि करें। रोजगार में कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। भौतिक इच्छाएं बलवती होंगी। अभिभावकों के भावनात्मक सहयोग से उत्साह में वृद्धि होगी।
सिंह	नकारात्मक चिंताओं का त्याग करें। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपनी पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। वर्तमान में आपको सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक दिशा में प्रयास करना चाहिए।
तुला	महत्वाकांक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी। घरेलू कार्यरें में अत्याधिक व्यय का योग है। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। परिवार में सुखद स्थिति प्रसन्नता लाएगी।
कन्या	किसी नये कार्य की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए मन केंद्रित होगा। नवीन योजनाओं द्वारा प्रगति होगी। जीवन साथी के साथ मधुरता कायम रखें।
वृश्चिक	परिश्रम का समुचित लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा।
धनु	मन सुंदर कल्पनाओं से प्रभावित रहेगा। नये संबंधों के प्रति निकटता बढ़ेगी। उपस्थित साधनों में सन्तुष्ट व तृप्त होने का प्रयत्न करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता अपेक्षित है।
कुंभ	राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। अच्छे कायरे के लिए प्रशंसनीय होंगे। शासन-सत्ता से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा।
मकर	विभागीय परिवर्तनों से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने अन्दर धैर्य व वाणी में मधुरता लावें। कुछ नई अभिलाषाएं मन में जागृत होंगी। प्रियजनों का सनिध्य प्राप्त होगा।
मीन	आवेश में किये गये कार्य से कष्ट संभव। भावनात्मक समस्याओं पर सगे-संबंधियों के बीच खुलकर बात करें। कुछ नये उत्साह व कार्य क्षमता की अनुभूति करेंगे।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय मुसलमानों की भूमिका

सैय्यद जाहिद अली रियासत
****

भारत की स्वतंत्रता का इतिहास विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों से संबंधित करोड़ों भारतीयों के सामूहिक संघर्ष और बलिदानों की कहानी है। इस राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय मुसलमानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हर मोर्चे पर योगदान दिया। कुछ ने रणभूमि में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कुछ ने पत्रकारिता के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया, जबकि अनेक धार्मिक विद्वानों ने जनचेतना जगाई और राजनीतिक नेताओं ने स्वतंत्र भारत की प्राप्ति की दिशा में आंदोलन का मार्गदर्शन किया। बहादुर शाह ज़फ़र, मौलवी मुहम्मद बाक़र, मौलाना फ़ज़ल-ए-हक़ ख़ैराबादी, सर सैयद अहमद ख़ान, हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी प्रमुख हस्तियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता,आज भी बहुत नहीं गर्व से याद किया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का योगदान न तो किसी एक क्षेत्र तक सीमित था और न ही किसी एक गतिविधि के क्षेत्र तक। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश विस्तारवाद के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध प्रस्तुत किया, बहादुर शाह ज़फ़र ने 1857 के विद्रोह के दौरान प्रतीकात्मक नेतृत्व प्रदान किया; मौलवी मुहम्मद बाक़र ने पत्रकारिता को प्रतिरोध का एक शक्तिशाली माध्यम बनाया; मौलाना फ़ज़ल-ए-हक़ ख़ैराबादी ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया; सर सैयद अहमद ख़ान ने शैक्षिक और सामाजिक सुधारों की नींव रखी; मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने संयुक्त राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन किया; हसरत मोहानी भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले शुरुआती नेताओं में शामिल थे; और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने राजनीतिक नेतृत्व, पत्रकारिता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया

भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र को भारतीय सैनिकों और क्रांतिकारियों ने विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि उनकी राजनीतिक सत्ता सीमित थी, फिर भी उनके नेतृत्व ने विभिन्न क्षेत्रों के स्वतंत्रता सेनानियों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट किया। विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून (वर्तमान का म्यांमार) निर्वासित कर दिया, जहाँ 1862 में उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी कविताएँ देशभक्ति, निर्वासन और अपनी मातृभूमि के प्रति गहरी लालसा की कालजयी अभिव्यक्ति बनी हुई हैं। मौलवी मुहम्मद बाक़र को उर्दू पत्रकारिता के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। प्रसिद्ध दिल्ली उर्दू अख़बार के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की कड़ी आलोचना की और 1857 के विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता के उद्देश्य का खुलकर समर्थन किया। अपने अडिग रुख के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 16 सितंबर 1857 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के पहले शहीद पत्रकार के रूप में माना जाता है। मौलाना फ़ज़ल-ए-हक़ ख़ैराबादी एक प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान, दार्शनिक और साहित्यकार थे। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का आह्वान करते हुए एक धार्मिक फतवा जारी किया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक और धार्मिक समर्थन प्राप्त हुआ। विद्रोह के दमन के बाद उन्हें गिरफ्तार कर अंडमान द्वीप समूह की सेल्युलर जेल में निर्वासित कर दिया गया, जहाँ उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अंततः वहीं उनका निधन हुआ। 1857 की घटनाओं के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने भारतीय मुसलमानों के शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की और मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। यद्यपि उन्होंने स्वतंत्रता के राजनीतिक संघर्ष में सीधे भाग नहीं लिया, लेकिन उनके शैक्षिक सुधारों ने ऐसे प्रबुद्ध नेताओं की एक पीढ़ी तैयार की, जिन्होंने आगे चलकर भारत के राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैयद फ़ज़ल-उल-हसन, जो हसरत मोहानी के नाम से प्रसिद्ध थे, एक प्रसिद्ध उर्दू कवि, पत्रकार और क्रांतिकारी नेता थे। वे भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले शुरुआती नेताओं में से एक थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कारावास का सामना किया और अपने लेखन, भाषणों तथा पत्रकारिता के माध्यम से देश को प्रेरित करते रहे। क्रांतिकारी नारा ÷इंक़लाब ज़िंदाबाद÷ (क्रांति अमर रहे) व्यापक रूप से उनसे जोड़ा जाता है और बाद में यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारों में से एक बन गया।मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। अपने समाचारपत्रों अल-हिलाल और अल-बलाग़ के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना की और जनता में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 1940 से 1946 के बीच स्वतंत्रता आंदोलन में निर्णायक नेतृत्व की भूमिका निभाई। वे हिंदू-मुस्लिम एकता के दृढ़ समर्थक थे और उन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया। स्वतंत्रता के बाद वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक संगठनों के विकास में उनका योगदान स्थायी महत्व रखता है।

यमन और सोमालिया के पास समुद्री लुटेरों ने 2 जहाजों को अगवा किया, 22 भारतीय

सना। यमन और सोमालिया के तट के पास हथियारबंद समुद्री लुटेरों द्वारा दो वाणिज्यिक जहाजों को अगवा किए जाने से क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। दोनों जहाजों पर कुल 22 भारतीय नागरिक सवार थे। पहला जहाज 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड क्षेत्र में और दूसरा जहाज 20 अगस्त को यमन के अल-मुकल्ला के पास अगवा किया गया।ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन विभाग के अनुसार, 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड क्षेत्र में मराया के पास करीब आठ हथियारबंद लोगों ने कैमरून के झंडे वाले जहाज एमवी-लुतुफ पर कब्जा कर लिया।जहाज पर चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। इनमें छह भारतीय नागरिक, एक तुर्की नागरिक, एक जॉर्जियाई नागरिक और एक सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल था। जहाज पर सैन्य उपयोग से जुड़ी सामग्री लदी हुई थी, जिसे तुर्की में सैन्य प्रशिक्षण के लिए ले जाया जा रहा थाअधिकारियों के अनुसार, समुद्री लुटेरे जहाज को सोमालिया के डंगोरोयो की ओर ले गए हैं। फिलहाल जहाज और उसके चालक दल के सदस्यों की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है।ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन विभाग के मुताबिक, 20 अगस्त को दूसरा जहाज एमटी-सिबु-1 यमन के अल-मुकल्ला से करीब 136 समुद्री मील पूर्व में अगवा किया गया। करीब छह हथियारबंद लोगों ने जहाज पर कब्जा कर लिया और उसे सोमालिया की दिशा में मोड़ दिया।इरिट्रिया के झंडे वाला यह तेल उत्पाद टैंकर था। जहाज पर कुल 20 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 16 भारतीय नागरिक थे। इसके अलावा सीरिया, सूडान और इराक के नागरिक भी चालक दल में शामिल थे।अधिकारियों के अनुसार, इस जहाज पर सवार सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि, जहाज को सोमालिया की ओर ले जाए जाने के कारण उसकी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।दोनों घटनाओं ने अदन की खाड़ी और सोमालिया के आसपास समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। लंबे समय तक अपेक्षाकृत कम हुई समुद्री डकैती की घटनाओं के बीच दो वाणिज्यिक जहाजों के लगातार अगवा होने से समुद्री परिवहन की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं।

विशेष रूप से भारतीय चालक दल के बड़ी संख्या में मौजूद होने के कारण भारत के लिए भी इन घटनाओं का महत्व बढ़ गया है।एमटी-सिबु-1 पर अमेरिका की ओर से प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जहाज के अगवा होने की घटना के बाद संबंधित एजेंसियां घटनाक्रम पर नजर रख रही हैं और चालक दल की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।

दोनों घटनाओं में जहाजों की आवाजाही और चालक दल की स्थिति को लेकर संबंधित समुद्री सुरक्षा एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं। आने वाले दिनों में जहाजों और उनमें सवार भारतीय नागरिकों की स्थिति पर और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

इमरान खान को चिकित्सा जांच के बाद फिर अडियाला जेल में डाला गया

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा अंतरराष्ट्रीय अस्पताल में कुछ देर की चिकित्सा जांच के बाद वापस अडियाला जेल भेज दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टरों द्वारा खान की स्थिति का आकलन करने और उन्हें हिरासत में रखना सुरक्षित पाए जाने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। इस दौरान अस्पताल के बाहर भारी सुरक्षा बल मुस्तैद रहा।पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि 73 वर्षीय संस्थापक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधी रात के आसपास चिकित्सा मूल्यांकन के लिए अस्पताल ले जाया गया और शुक्रवार तड़के जेल वापस ले आए।सूत्रों ने बताया कि इमरान को अस्पताल लाते समय अडियाला जेल से अस्पताल तक आवाजाही बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच की गई।

गुमशुदा लोगों की तलाश में पुलिस को 19 महीने में मिली बड़ी कामयाबी, 95 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे

नोएडा। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस ने गुमशुदा और अपहृत बालक-बालिकाओं के साथ-साथ लापता स्त्री-पुरुषों की सकुशल बरामदगी को प्राथमिकता देते हुए व्यापक अभियान चलाया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में 1 जनवरी 2025 से 31 जुलाई 2026 तक तीनों जोन में दर्ज गुमशुदगी के मामलों में पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित बरामद कर उनके परिवारों से मिलाया है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में कुल 3,348 स्त्री-पुरुषों की गुमशुदगी दर्ज हुई, जिनमें से 2,962 यानी 88.47 प्रतिशत लोगों को सकुशल बरामद किया गया। वहीं, बालक-बालिकाओं से संबंधित 650 अभियोग दर्ज हुए, जिनमें 619 यानी 95.23 प्रतिशत बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पुलिस के अनुसार गुमशुदा लोगों की तलाश में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों, सोशल मीडिया और मुखबिर तंत्र का इस्तेमाल किया गया। प्राप्त सूचनाओं का तकनीकी विश्लेषण कर पुलिस टीमों ने संभावित स्थानों पर दबिश और तलाश की। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सार्वजनिक स्थानों और आश्रय गृहों पर भी खोजबीन की गई। नोएडा जोन के नौ थाना क्षेत्रों में कुल 965 स्त्री-पुरुषों की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इनमें 540 महिलाएं और 270 पुरुषों समेत कुल 810 लोगों को सकुशल बरामद किया गया, जो 83.93 प्रतिशत है। इस जोन में 155 स्त्री-पुरुषों की बरामदगी अभी शेष है। इसी तरह 249 बालक-बालिकाओं से संबंधित अभियोग दर्ज किए गए, जिनमें 207 बालिकाएं और 29 बालक सहित कुल 236 बच्चों को बरामद किया गया।

पुलिस के अनुसार 13 बच्चों की बरामदगी अभी बाकी है। सेंट्रल नोएडा जोन के आठ थाना क्षेत्रों में 1,702 स्त्री-पुरुषों की गुमशुदगी दर्ज हुई। इनमें 1,159 महिलाएं और 396 पुरुषों समेत कुल 1,555 लोगों को सकुशल बरामद किया गया। बरामदगी का प्रतिशत 91.36 रहा। 147 लोगों की तलाश अभी जारी है। बच्चों से संबंधित 258 मामलों में 224 बालिकाओं और 28 बालकों समेत कुल 252 बच्चों को सकुशल बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक यहां बरामदगी का प्रतिशत 97.67 रहा। ग्रेटर नोएडा जोन के नौ थाना क्षेत्रों में 681 स्त्री-पुरुषों की गुमशुदगी दर्ज हुई। इनमें 405 महिलाएं और 192 पुरुषों सहित कुल 597 लोगों को सुरक्षित बरामद किया गया, जबकि 84 लोगों की तलाश जारी है। वहीं 143 बालक-बालिकाओं से संबंधित मामलों में 94 बालिकाओं और 37 बालकों सहित कुल 131 बच्चों को सकुशल बरामद किया गया। 12 बच्चों की तलाश अभी शेष है। पुलिस ने गुमशुदगी से जुड़े मामलों का विश्लेषण कर ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित किया है, जहां इस प्रकार की घटनाओं की संभावना अधिक पाई गई। नोएडा जोन में सदरपुर, सलारपुर, सेक्टर-37, बरोला और होशियारपुर को हॉटस्पॉट बनाया गया है। सेंट्रल नोएडा जोन में इलाहाबास, भंगेल, नयागांव, याकूबपुर, कुलेसरा, जलपुरा, गौर सिटी-1, राइस सिटी और चेरी काउंटी को चिन्हित किया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा जोन में कस्बा कासना, कस्बा जेवर और दादरी के रेलवे रोड चौकी क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इन क्षेत्रों में नियमित पुलिस गश्त, संदिग्ध लोगों की चेकिंग, सीसीटीवी निगरानी, बीट पुलिस की सक्रियता और स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ाई गई है। जरूरत के अनुसार इन हॉटस्पॉट का दोबारा मूल्यांकन कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की गुमशुदगी के मामलों में तलाश बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण होती है। कई बार परिवार गुमशुदगी की सूचना पुलिस को देर से देते हैं, जिससे शुरुआती 'गोल्डन पीरियड' का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

दिल्ली में मिनी सचिवालय की योजना पड़ी सुस्त, 13 में से सिर्फ 6 जिलों के लिए ही मिल सकी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के सभी जिलों में मिनी सचिवालय बनाने की योजना की गति धीमी है। यहां तक कि द्वारका सेक्टर 10 में बनने वाले मिनी सचिवालय के लिए गत जनवरी में सरकार की वित्त एवं व्यय समिति ने 212 करोड़ की मंजूरी दे दी थी, उसके बाद भी योजना आगे नहीं बढ़ सकी है। इसके लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से जमीन भी राजस्व विभाग को हस्तांतरित नहीं हो सकी है। जबकि सात जिलों में अभी जमीन की खोज भी पूरी नहीं हो सकी है। जबकि इस परियोजना को घोषित किए हुए करीब एक साल बीत चुका है। अभी तक पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी, और दक्षिण पूर्वी जिलों में ही निर्माण स्थल की पहचान हो सकी है।

उत्तरी जिले में मौजूदा डीएम कार्यालय के उन्नयन की तैयारी: दिल्ली सरकार की सभी 13 जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित करने की योजना है। सरकार का उद्देश्य जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की सेवाओं को एक ही परिसर में उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जिन छह जिलों में योजना पर काम आगे बढ़ा है, उनमें पूर्वी जिले में मंडावली स्थित जिला कार्यालय को अपग्रेड करने की योजना है, जबकि उत्तरी जिले में मौजूदा डीएम कार्यालय के उन्नयन की तैयारी है। उत्तरी पश्चिमी जिले के लिए कंझावला और दक्षिणी पश्चिमी जिले के लिए द्वारका सेक्टर-10 में व्यवस्था प्रस्तावित है। दक्षिणी जिले में साकेत तथा दक्षिणी पूर्वी जिले के लिए नए परिसर की योजना है। 13 जिलों के लिए बजट में 100 करोड़ का प्रविधान किया गया था।

पिछले साल रेखा गुप्ता ने मिनी सचिवालय की घोषणा की थी: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 12 अगस्त 2025 को सभी जिलों में मिनी सचिवालय की जरूरत की घोषणा की थी। इसके बाद दिसंबर 2025 में दिल्ली के राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 की गई और सभी 13 जिलों में आधुनिक मिनी सचिवालय स्थापित करने की योजना सामने आई। प्रस्तावित परिसरों में राजस्व कार्यालय, एसडीएम, एडीएम, तहसील, उप-पंजीयक सहित अन्य विभागों की सेवाएं एक छत के नीचे उपलब्ध कराने की योजना है।

दिल्ली में टीबी का कहर, 42 दिन में मिले 12 हजार से अधिक नए

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी में टीबी की चुनौती लगातार गंभीर होती जा रही है। विशेष स्क्रीनिंग अभियान के दौरान दिल्ली में महज 42 दिनों में 12,078 नए टीबी मरीज सामने आए। इस वर्ष 24 मार्च से पांच मई तक चले इस अभियान में 71,603 लोगों की जांच की गई, इनमें 1,323 बच्चे और 10,755 वयस्क शामिल थे। सामने आए मरीजों में करीब 42 प्रतिशत एक्स्ट्रा-पल्मोनरी टीबी से पीड़ित मिले।

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत इस वर्ष एक जुलाई तक दिल्ली में 28.83 लाख लोगों की स्क्रीनिंग, 21.67 लाख छाती के एक्स-रे और 3.65 लाख मॉलिक्यूलर टेस्ट किए गए। इस अभियान में अब तक 1.75 लाख टीबी मरीज नोटिफाई किए गए हैं।

लगातार तीन साल एक लाख से अधिक मामले: दिल्ली में टीबी का नोटिफिकेशन लगातार ऊंचा बना हुआ है। 2023 में 1,00,523, 2024 में 1,05,343 और 2025 में 1,12,977 मामले नोटिफाई हुए। यानी लगातार तीसरे वर्ष संख्या एक लाख से अधिक रही। 2019-21 के राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण में दिल्ली में टीबी की प्रसार दर 747 प्रति लाख आबादी मिली थी।

स्क्रीनिंग बढ़ने से सामने आ रहे छिपे मरीज: विशेषज्ञों के अनुसार स्क्रीनिंग में बड़ी संख्या में मरीज मिलने को सीधे टीबी संक्रमण बढ़ने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। सक्रिय खोज और जांच बढ़ने से ऐसे मरीज भी सामने आते हैं, जो पहले स्वास्थ्य व्यवस्था की नियमित निगरानी से बाहर थे।

होने वाली कुल मृत्यु में टीबी की हिस्सेदारी बढ़ी: दिल्ली सरकार के जन्म-मृत्यु आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005 से वर्ष 2024 के दौरान दिल्ली में टीबी से होने वाली कुल मौतों की संख्या 65,985 रही, इसे 2024 में सबसे अधिक 5,093 और सबसे कम 2007 में 2,516 थी। वर्ष 2024 में दिल्ली में होने वाली कुल मौतों में टीबी की हिस्सेदारी 4.86 प्रतिशत रही।

38 वार्डों पर विशेष निगरानी: दिल्ली के 11 जिलों के 38 उच्च जोखिम वाले वार्डों को विशेष निगरानी के लिए चिन्हित किया गया है। इन वार्डों में दिल्ली के 80 प्रतिशत से अधिक उच्च जोखिम वाले टीबी बोझ को कवर करने का अनुमान है। यहां सक्रिय खोज, एक्स-रे और मॉलिक्यूलर जांच बढ़ाने पर जोर है।

महाराष्ट्र में मराठी न बोलने वाले डेढ़ लाख ड्राइवरों ने सीखी मराठी, 7,750 परीक्षा में फेल; फिर देना होगा

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि गुरुवार को राज्यभर में हुई चेकिंग के पहले दिन कमर्शियल पैसेंजर गाड़ियों के 1,268 ड्राइवरों मुख्य रूप से टो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण नोटिस जारी किए गए। उन्होंने कहा कि ये नोटिस राज्यभर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा जारी किए गए थे। इन ड्राइवरों को राज्य की मुख्य भाषा की जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर उनके बैज तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिए जाएंगे। सरनाइक ने कहा कि गुरुवार शाम तक कुल 8,217 ड्राइवरों की जांच की गई, जिनमें मुंबई मेट्रोपालिटन रीजन के 3,995 ड्राइवर शामिल थे। 604 ड्राइवरों को मराठी की जरूरी जानकारी नहीं थी। राज्य के बाकी हिस्सों में 4,222 ड्राइवरों की जांच की गई और 664 को नोटिस जारी किए गए। उन्होंने कहा कि चेकिंग अभियान 30 सितंबर तक जारी रहेगा। मराठी की जरूरी जानकारी होना केवल नियमों का पालन करने का मामला नहीं है, बल्कि यह यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा से भी जुड़ा है। मई में यह घोषणा करने के बाद कि मराठी की बुनियादी जानकारी जरूरी है, राज्य सरकार ने उन ड्राइवरों के लिए मराठी का एक कोर्स शुरू किया जो मराठी नहीं बोल पाते। सरकार ने उनके लिए मराठी सीखने की समय-सीमा भी 15 अगस्त तय की थी। गुरुवार को चेकिंग ड्राइव के दौरान ड्राइवरों का 16 सवालों वाला टेस्ट लिया गया।

नजर उतारने का बहाने ट्रांसजेंडर बनकर फ्लैट में घुसा बदमाश, एयर होस्टेस से किया यौन

मुंबई, एजेंसी। मुंबई के पवई इलाके में एक एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है। आरोपी अनिल शिंदे ने ट्रांसजेंडर का भेष धरकर नजर उतारने के बहाने पीड़िता के फ्लैट में प्रवेश किया और उसके साथ जबरन अश्लील हरकतें कीं। हालांकि महिला के चिल्लाने पर वह डरकर भाग गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घटना मंगलवार दोपहर 12:20 से 12:50 के बीच हुई। शिंदे ट्रांसजेंडर का रूप धारण कर बिल्डिंग में घुसा और सिक्योरिटी गार्ड का विश्वास हासिल कर तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। उसने कई फ्लैटों पर दस्तक दी। पीड़िता का पति अस्पताल में भर्ती था। आरोपी ने परिवार पर पड़ी नजर उतारने का दावा कर फ्लैट में प्रवेश पा लिया। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उस पर पानी छिड़का, सिर पर हाथ रखा और बेडरूम में ले जाकर आंखें बंद करने और बिस्तर पर लेटने को कहा। इसके बाद उसने यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता के चीखने पर आरोपी 200 रुपये लेकर भाग गया। रात करीब 11 बजे पीड़िता सदमे की हालत में पुलिस स्टेशन पहुंची। महिला पुलिस अधिकारी ने उससे बातचीत कर पूरी घटना का पता लगाया। पवई पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी का पता लगाया।

चार घंटे के अंदर कलवा की झुग्गी बस्ती से शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और काला जादू संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी ने दावा किया कि उसका परिवार भीख मांगने के लिए ट्रांसजेंडर का भेष धरता है। पुलिस जांच कर रही है कि उसने पहले भी ऐसे अपराध किए हैं या नहीं। वहीं पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अजनबियों को फ्लैट में प्रवेश न दें और उनकी पहचान तथा मकसद की जांच जरूर करें।

पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों से संवाद के लिए 21 अगस्त को वेबीनार-2, मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन होंगे मुख्य

जयपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप संचालित पीएम श्री विद्यालयों को अपने-अपने क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने तथा उन्हें अनुकरणीय विद्यालयों के रूप में स्थापित करने की दिशा में शिक्षा विभाग द्वारा निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों से नियमित संवाद स्थापित करने की पहल की गई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन की पहल पर पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के साथ संवाद की इस श्रृंखला में 21 अगस्त, 2026 को प्रात 11 बजे राज्य स्तरीय'वेबीनार-2' का आयोजन जयपुर स्थित आरआईसी में किया जाएगा। वेबीनार का उद्देश्य पीएम श्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाना है। वेबीनार में स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों के निर्माण एवं रखरखाव, पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के प्रभावी संचालन, व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशल विकास तथा पीएम श्री योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में वृद्धि एवं व्यक्तित्व निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। वेबीनार में प्रदेश के सभी पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधान सहभागिता करेंगे। इस दौरान विद्यालय स्तर पर किए जा रहे नवाचारों एवं उपलब्धियों को साझा करने के साथ ही जमीनी स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी तथा उनके व्यावहारिक समाधान तलाशे जाएंगे। पीएम श्री विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और समग्र व्यक्तित्व निर्माण के आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में यह संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संवाद के माध्यम से विद्यालयों के अनुभवों को साझा करते हुए प्रभावी कार्यप्रणालियों को अपनाने और विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षिक वातावरण तैयार करने पर विशेष जोर रहेगा।

सुरक्षाबलों के खिलाफ झूठे प्रचार और सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर मंथन

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर के राज्यों में सोशल मीडिया पर झूठे नैरेटिव कैसे सुरक्षा के लिए नई चुनौती बनते जा रहे हैं, इस पर एक महत्वपूर्ण मंथन किया गया है। दरअसल यह देखा गया है कि कई बार सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सुरक्षा बलों के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। इसके जरिए लोगों की धारणा प्रभावित करने व अविश्वास पैदा करने का कुप्रयास किया जाता है। असम राइफल्स ने इस गंभीर चुनौती पर नई दिल्ली में आयोजित मेजर बॉब खाथिंग स्मृति व्याख्यान में बात की। यहां विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया के 'हथियारीकरण' से निपटने और पूर्वोत्तर में जनविश्वास मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। 'सोशल मीडिया का हथियारीकरण' व्याख्यान का मुख्य विषय रहा। कार्यक्रम में डीजी मिलिटरी ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस. पेंढारकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मेजर बॉब खाथिंग के जीवन का अध्ययन यह याद दिलाता है कि पूर्वोत्तर में नेतृत्व के लिए केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण को समझना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज को समझना भी उतना ही आवश्यक है।

पारीछा बांध बना विश्व धरोहर, फ्रांस में मिलेगा सम्मान

लखनऊ । योगी सरकार प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत को विश्व पटल पर पहचान दिलाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इस दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। झांसी के 140 साल पुराना पारीछा बांध अब वैश्विक विरासत का हिस्सा बन गया है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज आईसीआईडी ने वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स डब्ल्यूएचआईएस के रूप में मान्यता दे दी है। पारीक्षा बांध को फ्रांस में अक्टूबर में 26वीं आईसीआईडी इंटरनेशनल कांग्रेस और 77वीं इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउसिंल मीटिंग के दौरान डब्ल्यूएचआईएस अवार्ड-26 दिया जाएगा। प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन अनिल गर्ग ने बताया कि 13 अगस्त को विभाग को आईसीआईडी की ओर से एक पत्र भेजा गया था, जिसमें झांसी के 140 साल पुराने पारीछा बांध को फ्रांस के

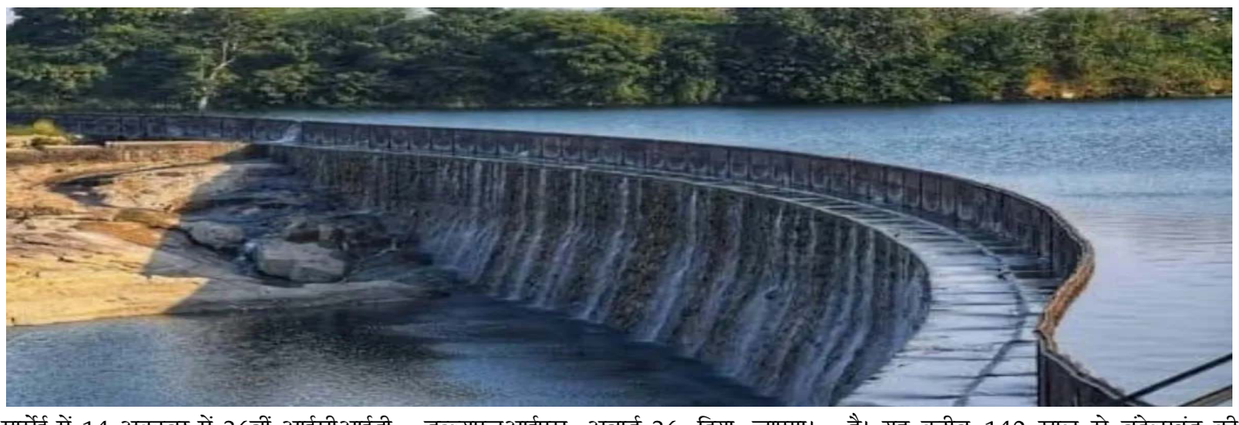

मार्सेई में 14 अक्टूबर में 26वीं आईसीआईडी इंटरनेशनल कांग्रेस और 77वीं इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउसिंल मीटिंग के दौरान डब्ल्यूएचआईएस अवार्ड-26 दिया जाएगा। विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। झांसी का पारीछा बांध बेतवा नदी पर बना है। यह करीब 140 साल से बुंदेलखंड की सिंचाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह बेतवा नहर प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। इस नहर व्यवस्था से बुंदेलखंड के सूखे क्षेत्रों में खेती के लिए पानी पहुंचाया जाता है। पारीछा बांध करीब 1,174 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई नदी तल से करीब 16.8 मीटर है। इसमें 318 स्टील के गेट लगाए गए हैं। इन गेटों की मदद से पानी को रोकने और जरूरत के हिसाब से छोड़ने का काम किया जाता है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में इसकी पानी जमा करने की क्षमता बढ़ाई गई है। पहले इसकी क्षमता करीब 1,700 मिलियन क्यूबिक फीट थी, जिसे बढ़ाकर करीब 2,400 मिलियन क्यूबिक फीट किया गया। यह बांध 140 साल पुराना होने के बाद भी काम कर रहा है। इस बांध से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सिंचाई का फायदा मिलता है। बारिश के मौसम में जब बांध के गेट खोले जाते हैं तो यहां पानी का सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है। यही वजह है कि यह जगह पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनती है। पारीछा बांध से थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पानी मिलता है। परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता 920 मेगावाट है। पारीछा बांध को विकसित करने की योजना 19वीं सदी में बनाई गई थी। 1855 में कैप्टन स्ट्रेची ने बुंदेलखंड के लिए नहर प्रणाली विकसित करने का विचार रखा था। इसके बाद सर्वे किया गया। 1881 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1886 में बांध चालू हो गया। पारीछा बांध को डब्ल्यूएचआईएस अवार्ड-26 अवॉर्ड के लिए चुना जाना सिर्फ एक पुराने बांध को सम्मान मिलना नहीं है। यह बुंदेलखंड की उस सिंचाई व्यवस्था की पहचान है, जो लंबे समय से किसानों और खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने में काम कर रही है। योगी सरकार प्रदेश में पुरानी जल संरचनाओं को सम्मान देने के साथ आधुनिक सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने पर कार्य कर रही है।

हुनरमंद युवा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत : कपिल देव

लखनऊ । योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को आधुनिक कौशल, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के लिए आईटीआई की प्रशिक्षण व्यवस्था में व्यापक बदलाव करने जा रही है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के राजकीय आईटीआई को पारंपरिक प्रशिक्षण केंद्रों तक सीमित न रखते हुए आधुनिक तकनीक, नए ट्रेड और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप भविष्य के कौशल एवं रोजगार केंद्र के रूप में विकसित करना है। बुधवार को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ स्थित प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागीय गतिविधियों का जायजा लेने के साथ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर प्रशिक्षण व्यवस्था, विभागीय योजनाओं की प्रगति तथा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयासों की समीक्षा की।बैठक में प्रदेशभर में संचालित राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रशिक्षकों की उपलब्धता, तकनीकी संसाधनों, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आधुनिक ट्रेडों तथा प्रशिक्षार्थियों को रोजगार से जोड़ने की तैयारियों पर विस्तार

से चर्चा हुई।श्री अग्रवाल ने कहा कि युवाओं के सीखने का तरीका तेजी से बदल रहा है और डिजिटल माध्यमों तथा नई तकनीकों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कौशल प्रशिक्षण को भी आधुनिक, तकनीक आधारित और रोजगारपरक बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिजिटल लर्निंग, आधुनिक तकनीक और उद्योगों की जरूरतों को प्रशिक्षण व्यवस्था से जोड़ा जाए तथा आईटीआई में उपलब्ध तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। आईटीआई युवाओं के लिए बेहतर करियर और रोजगार का मजबूत माध्यम है। विद्यार्थियों में आईटीआई के प्रति आकर्षण और विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों को आईटीआई के आधुनिक ट्रेडों, रोजगार की संभावनाओं और कौशल आधारित करियर विकल्पों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि आईटीआई में आधुनिक और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देकर प्रशिक्षण व्यवस्था को युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए। कौशल प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल युवाओं को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के योग्य बनाना है। इसके लिए आईटीआई और उद्योगों के बीच समन्वय को और मजबूत करने तथा इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ प्रशिक्षण में तकनीकी दक्षता के अलावा कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, इंटरव्यू और कार्यस्थल की आवश्यक क्षमताओं को शामिल करने पर जोर दिया।श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के आईटीआई को नई तकनीक, आधुनिक ट्रेड और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य के कौशल केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि हुनरमंद युवा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हैं। योगी सरकार का लक्ष्य है कि आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला प्रत्येक युवा अपने कौशल के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार हासिल करे और प्रदेश की आर्थिक प्रगति में सक्रिय भागीदार बने।इस अवसर पर प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम निदेशक प्रशिक्षण अभिषेक सिंह सहित विभाग एवं निदेशालय के अधिकारी उपस्थित रहे।

शिक्षामित्र और अनुदेशक के बाद रसोइयों की बारी,बढ़ेगा मानदेय !

रसोइयों की 1000 महीना हो सकती है बढ़ोतरी

लखनऊ। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों का मानदेय बढ़ने के प्रबल आसार है। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले उनको तोहफा देने की तैयारी में है। एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव मिड-डे मील अथॉरिटी ने भेज दिया है।उच्च स्तर पर बैठक में सहमति बन चुकी है।रसोइयों को अभी 2,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। यूनिफॉर्म के लिए 500 रुपये अलग से दिए जाते हैं, जो उनके खाते में पहुंचते हैं। 400 रुपये ग्लव्ज के लिए मिलते हैं लेकिन वह स्कूल प्रबंधन समिति के खाते में जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार एक बार फिर रसाइयों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी कर रही है। एमडीएम प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। उम्मीद है जल्द इस पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री खुद बढ़े हुए मानदेय का ऐलान कर सकते हैं।अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। सरकार किसी बड़े तबके को नाराज नहीं रखना चाहती। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया जा चुका है। शिक्षकों, शिक्षा मित्रों से लेकर रसोइयों तक को कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। यूपी में रसाइयों की संख्या 3.53 लाख है और ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। इनका मानदेय पांच साल से नहीं बढ़ा और लगातार इसके लिए मांग उठ रही है। चुनाव से पहले इनका मानदेय बढ़ाकर बड़े वर्ग को सरकार खुश करना चाहती है।

जापानी तकनीक और यूपी की औद्योगिक क्षमता से बनेगा निवेश का नया अध्याय

लखनऊ । यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 के उद्घाटन एवं दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जापान और भारत के प्रमुख उद्योग समूहों ने उत्तर प्रदेश को निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ केंद्र बताया। समारोह में कुबोटा कॉरपोरेशन जापान और स्पार्क मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में अपने निवेश, साझेदारी के अनुभव और भविष्य की संभावनाओं को साझा किया। दोनों उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए प्रदेश में उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल मानव संसाधन, बड़े बाजार, निवेश-अनुकूल नीतियों और सरकार के सहयोग को औद्योगिक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण आधार बताया।समारोह में कुबोटा कॉरपोरेशन, जापान के प्रेसिडेंट एवं सीईओ शिंगो हानाडा ने नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग को कंपनी के लिए महत्वपूर्ण माइलस्टोन बताते हुए कहा कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में कुबोटा की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और साझेदारी को एक नया विस्तार मिल रहा है। उन्होंने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इन्वेस्ट यूपी और उन सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके समर्थन और सहयोग से यह महत्वपूर्ण पड़ाव संभव हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश भारत के सबसे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक केंद्रों में से एक के रूप में उभरा है। 135 वर्षों से अधिक समय से कुबोटा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और समाज में योगदान देने के उद्देश्य से काम कर रहा है। कंपनी की फिलॉसफी के अनुरूप वह बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए लोगों के हित में काम करती रहेगी। स्पार्क मिंडा की यूपी में 40 वर्षों से अधिक की मौजूदगी, अब बड़े स्तर पर विस्तार की तैयारी' समारोह में आकाश मिंडा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में कंपनी की मौजूदगी और भविष्य की योजनाओं पर अपने विचार रखे। उत्तर प्रदेश आज संभावनाओं और नए अवसरों का प्रदेश है। आकाश मिंडा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण के लिए मजबूत फाउंडेशन तैयार हुआ है। आकाश मिंडा ने बताया कि वह स्पार्क मिंडा ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कंपनी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी की उत्तर प्रदेश में 40 वर्षों से अधिक समय से मौजूदगी है और वर्तमान में प्रदेश में 9,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्पार्क मिंडा के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है और कंपनी यहां अपनी मौजूदगी को कहीं बड़े स्तर पर विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है।

यूपी में निवेश करें, हर स्तर पर मिलेगा सहयोग : योगी

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट के दौरान प्रमुख कंपनियों के सीईओज व बिजनेस लीडर्स के साथ आयोजित राउंड टेबल मीटिंग में निवेशकों का प्रदेश में निवेश के प्रति उत्साह दिखाने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में 360 डिग्री का व्यापक परिवर्तन हुआ है। इसी बदलाव के कारण आज उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख और ड्रीम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभरकर सामने आया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों और कंपनियों को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने निवेशकों का आह्वान करते हुए कहा कि वे उत्तर प्रदेश आएं और यहां औद्योगिक एवं कारोबारी गतिविधियों का विस्तार करें। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशकों को किसी

भी स्तर पर परेशानी का सामना न करना पड़े। इन्वेस्टमेंट मीट को लेकर जिस तरह की उत्सुकता प्रमुख उद्योगपतियों और सीईओज ने दिखाई है, उसके लिए वह सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। निवेशकों की ओर से दिए गए सुझावों को प्रदेश सरकार की टीम ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। सरकार और उसकी टीम निवेश अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के पास बड़ी संख्या में युवा मैनपावर है। सरकार युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप स्किलिंग और अपस्किलिंग के अवसर उपलब्ध करा रही है। इससे निवेशकों को प्रशिक्षित और सक्षम मानव संसाधन उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाला निवेश निवेशकों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। प्रदेश सरकार अपनी नीतियों के दायरे में निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार केवल घोषणाएं करने में विश्वास नहीं करती बल्कि जो कहती है उसे धरातल पर उतारती है। पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में आए बदलाव को निवेशक स्वयं देख सकते हैं। कानून-व्यवस्था, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक वातावरण और निवेश के लिए तैयार नीतियों से आए बदलाव ने उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर पेश की है। सरकार की कार्यप्रणाली में आया यह बदलाव निवेशकों को भी दिखाई देगा।मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टमेंट मीट को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया। सीएम ने विश्वास जताया कि प्रमुख उद्योग समूहों की उत्तर प्रदेश में बढ़ती रुचि से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को और गति मिलेगी। निवेशकों से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने और प्रदेश में निवेश के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया।

राजस्थान में हरीश द्विवेदी के संगठनात्मक अनुभव का लाभ लेंगी भाजपा

लखनऊ। राजस्थान में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के संगठनात्मक अनुभव का लाभ भजपा लेंगी। पार्टी ने पूर्व सांसद श्री द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से 17 अगस्त 2026 को घोषित नई राष्ट्रीय टीम में श्री द्विवेदी समेत उत्तर प्रदेश के आठ नेताओं को महत्वपूर्ण दायित्व मिला है।

हरीश द्विवेदी बस्ती लोकसभा सीट से 2014 और 2019 में भाजपा के टिकट पर लगातार दो बार सांसद चुने गए थे। श्री द्विवेदी वर्तमान में असम भाजपा के प्रभारी के रूप में भी संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लगातार मिल रही संगठनात्मक जिम्मेदारियों को भाजपा में उनके अनुभव और संगठनात्मक भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है।

हरीश द्विवेदी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। इसके बाद उन्होंने भाजपा संगठन में विभिन्न

जिम्मेदारियां निभाई और 2014 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे चुनावी राज्यों में संगठनात्मक अनुभव का इस्तेमाल भाजपा की चुनावी रणनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरीश द्विवेदी का जन्म 22 अक्टूबर 1973 को एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था,उनके पिता श्री साधुशरण दुबे किसान इंटर कालेज में शिक्षक रहे हैं। सर्वप्रथम इन्होने वर्ष 1990 से 1992 तक अपने ग्राम सभा की संघ शाखा में में मुख्य शिक्षक के रूप में कार्य किया, 1991 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आये, 1993 से 95 तक विद्यार्थी परिषद, बस्ती के जिला प्रमुख रहे। वह 1994 से 1996 तक प्रदेश सहमंत्री रहे। वह 1995 से 98 तक एबीवीपी गोरखपुर के विभाग संगठन मंत्री भी बनें। 1998 से 2000 तक प्रयाग में विभाग संगठन मंत्री रहे,वर्ष 2000 से 2003 तक प्रयागराज व सुल्तानपुर विभाग के संगठन मंत्री रहे, 2004 से भाजपा के सम्पर्क आये,2005 से 2007 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी के राजनीतिक सलाहकार रहे। इस दौरान वह 2005 से 2007 तक भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री भी रहे, 2007 से 2010 तक भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। श्री द्विवेदी 2010 से 2013 तक भाजयुमो की यूपी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने भाजयुमो द्वारा सक्रिय रूप से तिरंगा यात्रा में भाग लिया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बस्ती सदर विधान सभा क्षेत्र से टिकट मिला, 2013 से अब तक वह भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं । हरीश जी वर्ष 2014 व 2019 के आम चुनावों में भाजपा प्रत्याशी के रूप में बस्ती संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुकें हैं । सांसद बनने के उपरांत हरीश जी विभिन्न संसदीय समितियों जैसे- ऊर्जा,सूचना और प्रौद्योगिकी,वित्त,प्राकलन व याचिका संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं/ रह चुके हैं । हरीश जी जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में बनी भाजपा की राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्व का भी निर्वहन कर चुके हैं एवं बिहार जैसे महत्त्वपूर्ण प्रदेश सह प्रभारी भी रहे हैं।

भारत और नाइजीरिया के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध : केशव

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकारी आवास 7 कालिदास मार्ग पर नाइजीरिया के संघीय गणराज्य के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री एवं प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सीनेटर डॉ. अलियु साबी अब्दुल्लाही तथा उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं पर आधारित थी, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों, विशेष रूप से एफडीआर तकनीक एवं कार्बन फुटप्रिंट को कम करने वाली तकनीकों, के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण विभाग की उपलब्धियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों पर विस्तार से चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नाइजीरियई प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत औरनाइजीरिया के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंध रहे हैं तथा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अनुभवों एवं तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 'हर गांव में पक्के मार्ग और पुल उपलब्ध कराना हमारी सरकार का लक्ष्य है। गांव विकसित होगा तो प्रदेश विकसित होगा और प्रदेश के विकास के साथ प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली आएगी।' ग्रामीण सड़कें गांवों को केवल शहरों से जोड़ने का कार्य नहीं करतीं, बल्कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा हैं। अच्छी सड़क होने से किसान अपनी उपज को आसानी से बाजार तक पहुंचा सकता है, विद्यार्थियों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलते हैं, मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग एवं रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। सड़क संपर्क बेहतर होने से ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश का वातावरण बनता है और छोटे उद्यमों, कृषि आधारित उद्योगों तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए नई संभावनाएं पैदा होती हैं। इससे गांवों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता कम होती है।

फार्मासिस्ट भर्ती की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियो डिप्टी सीएम से मिले

लखनऊ । राजधानी लखनऊ में फार्मासिस्ट भर्ती की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने भर्ती में खाली पदों की संख्या के आधार पर सीटें बढ़ाने की मांग रखी। अभ्यर्थियों ने कहा कि विभाग में फार्मासिस्ट के कई पद रिक्त हैं। ऐसे में भर्ती की सीटें बढ़ाई जाएं, ताकि अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी का अवसर मिल सके। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बताया कि इस मामले में डीजी हेल्थ और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन से पहले ही बात की जा चुकी है। उन्होंने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांग पर सरकार की ओर से हर संभव रास्ता तलाशा जाएगा। कानूनी तौर पर जो भी विकल्प संभव होगा, सरकार अभ्यर्थियों की मदद करेगी। डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. शक्ति सिंह साधू (प्रधान सम्पादक), डॉ. प्रवीण (प्रबंध सम्पादक), एडवोकेट शैलेन्द्र श्रीवास्तव (कानूनी सलाहकार), राकेश अग्रवाल (जिला ब्यूरो उत्तर प्रदेश) अब्दुल नासिर स्टेट ब्यूरो उत्तर प्रदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शक्ति सिंह द्वारा राज तरूण आफसेट, एल0जी0एफ0 5–14, अंसल सिटी सेंटर, हजरतगंज, लखनऊ– 226001 से मुद्रित तथा 486/238–डी, डालीगंज, निरालानगर, जनपद लखनऊ–226020 से प्रकाशित।

सम्पादक– शक्ति सिंह मो0 7052608007 नोटः समाचार पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।